



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 1994/ वैशाख 14, 1916

No. 225]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 1994/VAISAKHA 14, 1916

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 1994

का. आ. 356(अ) :—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना स. 60(अ) तारीख 27 जनवरी 1994 (जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने जब तक उस सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो, तब तक किसी परियोजना के आरम्भ किए जाने वाले क्रिया-कलाप या नई परियोजना के विस्तारण या आधुनिकीकरण के संबंध में कतिपय निर्बन्धन और प्रतिषेध अधिरूपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन किया जाना चाहिए;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबन्ध है कि “उपनियम (3) में किसी बात के होने हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसा करना लोकहित में है वह उप नियम (3) के खंड (क) के अधिन सूचना देने की अपेक्षा में अभिमुखित हो सकेगी”;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधिन सूचना की अपेक्षा का अभि-मोचन करना लोकहित में है;

अतः केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 को नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

2. उक्त अधिसूचना में :—

(1) पैरा 2 में :—

(क) उपपैरा 1, में,—

(i) मद (क) में “उनके साथ परियोजना की ब्यौरेवार रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट और केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग दर्शक सिद्धांत के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण प्रबंध योजना होगी” शब्दों के स्थान पर “उनके साथ परियोजना की रिपोर्ट होगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई पर्यावरण संबंधी प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंध योजना सम्मिलित होगी”; शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद (ख) में,—

(I) “कार्य योजना” दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर “योजना” शब्द रखा जाएगा

(II) “अपूर्ण आंकड़ों का” शब्दों के स्थान पर “प्रपूर्ण आंकड़ों या योजना का” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपपैरा II में,—

(i) मद (घ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(ङ.) 500 हैक्टर से अधिक क्षेत्र में मुख्य खनिजों का पूर्वेक्षण आरंभ होगा।”

(ii) “उत्त स्थल अनापत्ति” शब्दों से आरंभ होने वाले और “विधायक मान्य होगा” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“उत्त स्थल अनापत्ति स्थापित अवकाश के लिए दी जाएगी और यह सन्निर्माण, संक्रिया या खनन आरंभ करने के लिए पात्र वर्ष का अवधि के लिए विधिमान्य होगी।”;

(ग) उपपैरा III में,—

(i) मद क में,—

(I) “संक्षिप्त साक्ष्यता रिपोर्ट” शब्दों के स्थान पर “रिपोर्ट” शब्द रखा जाएगा,

(II) “यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति के परामर्श में मूल्यांकन और निर्धारण किया जाएगा” शब्दों के स्थान पर “मूल्यांकन और निर्धारण प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा” किया जाएगा और यदि आवश्यक समझे जाए तो वह इस अधिसूचना की अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट संरचना वाली विशेषज्ञ समिति से परामर्श कर सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे,

(III) “संबंधित” शब्द का लोप किया जाएगा,

(ii) मद (ग) में, “प्रभाव निर्धारण अभिकरण” शब्दों से आरंभ होने वाले और “आरंभ नहीं किया जा सकेगा” शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(ग) प्रभाव निर्धारण अभिकरण, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दिए गए दस्तावेजों और आंकड़ों जो स्थलो अथवा कारखानों में मात्राओं के दौगन, यदि कोई गई हो, संगृहीत आंकड़ों द्वारा अनुपूरित होंगे, के तकनीकी निर्धारण और प्रभावित जनसंख्या की ओर यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण संबंधी समूहों को अंतः किया पर आधारित सिफारिशें तैयार करेगा। रिपोर्टों का मार्गण, सिफारिश और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, लोकहित के अधीन रहते हुए, संबंधित पक्षकारों या पर्यावरण संबंधी समूहों के अनुरोध पर उल्लेख कराई जाएगी। जनता के विचार, यदि प्रभाव निर्धारण अभिकरण द्वारा प्रस्ताव को प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसा विनिश्चय किया जाए तो इस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित लोक सुनवाई में ऐसी सुनवाई की कम से कम दो समाचार पत्रों में एक मास की सूचना देने के पश्चात्, मांगे जा सकेंगे। जनता को लोक हित के अधीन रहते हुए, रिपोर्ट/पर्यावरणीय प्रबंध योजनाओं तक पहुंच की व्यवस्था प्रभाव निर्धारण अभिकरण के मुख्यालय में, की जाएगी।

निर्धारण, परियोजना प्राधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेजों और आंकड़ों की प्राप्ति से नब्बे दिन की अवधि से भीतर और जहां अपेक्षित हो वहां लोक सुनवाई को समाप्ति पर पूरा किया जाएगा और विनिश्चय उसके पश्चात् तीस दिन के भीतर सूचित कर दिया जाएगा।

दी गई अनापत्ति, सन्निर्माण या संक्रिया के प्रारंभ होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(III) क. परियोजना के स्थापित किए जाने से संबंधित कोई प्रारंभिक या अन्य सन्निर्माण कार्य पर्यावरणी और स्थल अनापत्ति प्राप्ति किए जाने तक आरंभ नहीं किया जा सकेगा।

(घ) उपपैरा iv के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“IV प्रभाव निर्धारण अभिकरण को, सिफारिशों के कार्यान्वयन और उन शर्तों को जिनके अधीन पर्यावरण संबंधी अनापत्ति दी गई है, प्रभावों रूप में मानोदर करने के लिए समर्थ प्रदान की दृष्टि से संबंधित परियोजना प्राधिकारी प्रभाव निर्धारण अभिकरण को छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। प्रभाव निर्धारण अभिकरण तैयारी के प्रयत्न रहते हुए; अनापत्ति रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएंगी।

(2) पैरा 3 में,—

(i) मद (क) में, “और का. ग्रा. सं. 319 (अ) 7 मई, 1992” अक्षर, शब्द, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर “का. ग्रा. सं. 416 (अ) तारीख 20 जून, 1991 और का. ग्रा. सं. 319(अ) तारीख 7 मई, 1992” अक्षर, शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) मद (ख) में, “19, 25” अंकों के स्थान पर “19, 21, 25” अंक रखे जाएंगे ;

(3) अनुसूची 1 में, मद 20 और उससे संबंधित प्रतिष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् “20. 5 हेक्टर से अधिक के लिए पट्टे सहित खनन परियोजनाएं (मुख्य खनिज)।” ;

(4) अनुसूची 3 की, मद 1 में आरंभिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

“1. समितियों का गठन निम्नलिखित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से होगा :” ।

[सं. जेड-12013/4/89-I ए-1]

के. के. बक्शी, अपर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम, कां.आ. 60(अ) दिनांक 27 जनवरी, 1994 द्वारा जारी किया गया था; उपरान्त कां.आ. 230(अ) दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा संशोधित किया गया ।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th May, 1994

S.O. 356(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No. S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernization of any activity or the undertaking of any project, unless environmental clearance has been granted by that Government ;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended ;

And whereas sub-rule 4 of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, “Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) ;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

2. In the said notification,—

(1) in paragraph 2,—

(a) in sub-paragraph I,—

(i) in item (a), for the words “a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management Plan”, the words “a project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report/Environment Management Plan” shall be substituted;

(ii) in item (b).—

(I) for the words “Action Plans” in both the places where they occur, the word “Plan” shall be substituted;

(II) for the words “incomplete data for”, the words “incomplete data or plans for” shall be substituted;

(b) in sub-paragraph II,—

(i) after item (d), the following item shall be inserted, namely:—

“(e) prospecting and exploration of major minerals in areas above 500 hectares.”;

(ii) for the portion beginning with the words “The said site clearance” and ending with the words “construction, operation or mining”, the following shall be substituted, namely:—

“The said site clearance shall be granted for a sanctioned capacity and shall be valid for a period of five years for commencing the construction, operation or mining.”;

(c) in sub-paragraph III,—

(i) in item (a).—

(I) for the words “The summary feasibility report”, the words “The reports” shall be substituted,

- (II) for the words "Agency at the Central Government in consultation with", the words "Agency, and if deemed necessary it may consult", shall be substituted.
- (III) the word "concerned" shall be omitted;
- (ii) in item (c), for the portion beginning with the words "The Impact Assessment Agency" and ending with the words "environmental site clearance is obtained", the following shall be substituted, namely:—
- “(c) The Impact Assessment Agency shall prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data, furnished by the project authorities, supplemented by data collected during visits to sites or factories, if undertaken, and interaction with affected population and environmental groups, if necessary. Summary of the reports, the recommendation and the conditions, subject to which environmental clearance is given, shall be made available subject to the public interest to the concerned parties or environmental groups on request. Comments of the public may be solicited, if so decided by the Impact Assessment Agency, within thirty days of receipt of proposal, in public hearings, arranged for the purpose, after giving thirty days notice of such hearings in at least two newspapers. Public shall be provided access subject to the public interest to the summary of the reports|Environmental Management Plans at the Headquarters of the Impact Assessment Agency.
- The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the project authorities and completion of public hearing, where required, and decision conveyed within thirty days thereafter.
- The clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation.
- III A. No construction work, preliminary or otherwise, relating to the setting up of the project may be undertaken till the environmental and site clearance is obtained.
- (d) for sub-paragraph IV, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- “IV. In order to enable the Impact Assessment Agency to monitor effectively the implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half yearly report to the Impact Assessment Agency. Subject to the public interest the Impact Assessment Agency shall make compliance reports publicly available.”;
- (2) in paragraph 3,—
- (i) in item (a), for the letters, words, brackets and figures “and S.O. No. 319 (E) dated 7th May, 1992” the letters, words, brackets and figures “S.O. No. 416(E) dated 20th June, 1991 and S.O. No. 319 (E) dated the 7th May, 1992” shall be substituted;
- (ii) in item (b), for figures “19, 25”, the figures “19, 21, 25” shall be substituted;
- (3) in Schedule 1, for item 20 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:
- “20. Mining projects (major minerals) with leases more than 5 hectares.”;
- (4) in Schedule III, in item 1, for opening paragraph, the following shall be substituted:—
- “1. The Committees will consist of experts in the following disciplines :”
- [No. Z-12013|4|89-IA-II]  
K. K. BAKSI, Addl. Secy.
- Footnote : The principal notification was issued vide No. S.O. 60(E) dated 27th January, 1994 and subsequently amended vide No. (1) S.O. 230(E), dated the 17-3-1994.